



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 17 मई, 2004/27 वैशाख, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार :

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 5 मई, 2004

संख्या-लो० नि० (ख) 7(1) 106/03.—यन: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चरोटी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-70 शूकराला पुल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाह्वती, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाह्वती, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के कार्यालय में निरोक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : हमीरपुर

तहसील : नादीन

गांव	खसरा नं०		क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
	साविक	हाल			
चरोटी	51/1	51/1/1	0	08	41
		52 सालम	0	00	23
		53/1/1	0	02	78
		कित्ता .. 3	0	11	42

शिमला-2, 6 मई, 2004

संख्या पी०बी०डब्ल्यू(बी)ए(7) 1-101/01.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सीछ/583, तहसील पधर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-20 (पठानकोट-चक्की-मण्डी), के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी

तहसील : पधर

गांव	खसरा नं०		क्षेत्र बीघा बिस्वा बिश्वांसी		
सीछ/583	483/1		0	12	13
	कित्ता .. 1		0	12	13

शिमला-2, 16 अप्रैल, 2004

संख्या पी०बी०डब्ल्यू०(बी) ए (7) 1-103/03.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव उप-मुहाल सरस्वतीनगर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में सरस्वती नगर-आन्टी मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

5. यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश शिमला के निर्णय दिनांक 27-5-2003 जो सिविल पेटिसन नं० 126/1996, ईश्वर सिंह रावन विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार में दिया गया था एवं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर रिब्यू पेटिसन दिनांक 1-4-2004 जो स्पेशल लीव टू. अपील (सी०) सी० सी० नं० 11259 आफ 2003 के विरुद्ध है, पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अन्तिम निर्णय की शर्तों के अधीन जारी की जाती है।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : जुब्बल

उप मुहाल	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
सरस्वतीनगर	1606 (हाल) 526 (साविक)	0 09 18
	किता .. 1	0 09 18

शिमला-2, 26 अप्रैल, 2004

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० बी० ए० (7) 1-52/2002.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चकरोत, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में चन्द्रनगर-हलाईला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : कोटखाई

गांव 1	खसरा नं० 2	क्षेत्र (हेक्टेयर में) 3
चकरोत	305/156	5 8
	264/44	1 1
	263/44	2 0
	163/1	0 5
	162/1	1 19
	162	0 5
	146	5 19
	143	0 5
	145	0 10
	4	2 5
	166	6 19
	203	2 17
	192	4 18
	316/141	1 13
	319/142	0 7
	125	4 3
	317/141	2 9
	318/142	0 3
	190	2 16
	42	1 5
	43	2 0
	28	3 16
	32	8 14
	33	1 16
	1	0 4
	2	2 6
	8	1 13
	9	4 3
	16	0 11
	17	14 5
	30	3 0
	31	1 18

1

2

3

6	1	1
68	1	2
69	2	3
70	0	9
119	1	2
74/1	0	4
111	1	3
116	0	9
117	0	5
120	1	11
118	0	5
124	0	2
121	3	10
106	1	7
107	0	14
112	0	15
114	1	11
204	5	2
230	1	10
249	1	17
242	1	4
243	0	19
248	0	14
246	0	3
247	0	14
229	7	16
251	1	4
144	1	0
123	0	6

किता .. 61

131 15

शिमला-2, 27 अप्रैल, 2004

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 85/03.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव लाठी, तहसील कुमारसैन,

जिला शिमला में ओडी-जोगसा-कुमारसैन सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : कुमारसैन

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयर म)
लाठी	472	0 03 66
कित्ता . . 1		0 03 66

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।